(b) if so, what is likely to be annual expenditure on account of unemployment allowance; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor?]

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि देश में बेरोजगारी के यथार्थ आंकड़े मालूम नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं का पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरे, आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए देश के स्वल्प साधनों का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा, जिससे उत्पादन रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अतः इस प्रकार का प्रस्ताव न तो व्यावहारिक माना जाता है और न ही आर्थिक दृष्टि से संभव।

t[THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Since precise estimates of unemployment in the country are not known, the financial implications of such a measure cannot be ascertained. Secondly, it would be more appropriate to utilise, the scarce resources of the country for schemes of economic development which will give rise to productive employment. Such a measure is, therefore, considered neither practical nor economically feasible,]

APPOINTMENT OF INDIAN AMBASSADOR TO HANOI

370. SHRI BHUPESH GUPTA : SHRI BALACHANDRA MENON : SHRI S. G. SARDESAI: SHRI YOGENDRA SHARMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the decision taken by Government sometime back to appoint an ambassador to Hanoi has not yet been implemented; and

(b) If so, what are the reasons for the delay in implementing the decision?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Ambassador to Hanoi has not yet been appointed. The final selection is expected to be made very soon.

(b) The delay arose because a careful choice had to be made for this important diplomatic assignment.

संयुक्त राष्ट्र का वायमंडल के परिवेशात्मक प्रदूषण से संबंधित सम्मेलन

371. श्री सीताराम केसरी :
श्री काली मुखर्जी :
श्रीमती प्रतिभा सिंह .
डा० भाई महावीर :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुमंडल के परिवेशात्मक प्रदूषण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 तथा 6 जन 1972 को जो सम्मेलन हुआ था क्या उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो वायुमंडल के परिवेशात्मक प्रदूषण को रोकने के लिए सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पो का ब्यौरा क्या है और उसमें कितने देशों ने भाग लिय था?

t[ ] English translation.

U. N. CONFERENCE ON ECOLOGICAL POLLUTION OF ATMOSPHERE

371. SHRI SITARAM KESRI: SHRI KALI MUKHERJEE : SHRIMATI PRATIBHA SINGH: DR. BHAI MAHAVIR : SHRI K. P. SINGH DEO :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an Indian delegation participated in the Conference of the United Nation Organisation on ecological pollution of atmosphere held on 5th and 6th June, 1972; and

(b) if so, what are the details of the resolutions passed in the conference for putting a stop to the ecological pollution of atmosphere and what is the number of participant countries ?]

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 5 से 16 जून, 1972 तक स्टाकहोम में हुआ था। इसमें कई निर्णय लिए गए थे और उनपर कई प्रस्ताव पास किए गए। महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

सम्मेलन में मानव पर्यावरण पर घोषणा स्वीकार की गई जिसमें विकसित और विकासमान दोनों प्रकार के देशों के लिए सहमत कार्यवाही को न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा बताई गई है। इसमें पर्यावरण की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को मान्यता दी गई है, जैसे अपर्याप्त जल व्यवस्था, समुद्र दूषण, अधिक नगरीकरण और गरीबी तथा अर्द्ध-विकास के साथ गंदगी की समस्या।

सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विवक्षा के विषय पर एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि पर्यावरण की रक्षा और उसकी वृद्धि का दायित्व मुख्यतः सरकारों पर है और उसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर प्रभावकारी ढंग से निभाया जा सकता है। उसमें सभी देशों की प्रभुसत्ता को मान्यता दी गई और यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों को अपने विकास कार्यक्रमों के अनुरूप पर्यावरण संबंधी नीतियों पर अमल करने में सहायता देने की आवश्यकता है। संगठन विवक्षा पर प्रस्ताव में भी यह सिफारिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 54 सदस्यों की गवनिंग काउन्सिल स्थापित करे जो कि समान भौगोलिक वितरण के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएं। गवनिंग काउंसिल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के माध्यम से महासभा को हर वर्ष रिपोर्ट भेजेगी और वह पर्यावरण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगी, सामान्य नीति की रूप-रेखा बताएगी, पर्यावरण स्थिति को ध्यान में रखेगी और संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अन्य व्यावसायिक समुदायों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की प्राप्ति, आकलन और आदान-प्रदान में योगदान को बढ़ावा देगी और विकासशील देशों पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों और उपायों के प्रभाव की निरंतर समीक्षा करेगी तथा पर्यावरण कार्यक्रमों और प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन में विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च की समस्याओं पर भी विचार करेगी।

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें विशेषकर वातावरण में किए गए अणु आयुध परीक्षणों की निंदा की गई। इसमें अणु परीक्षण करने के इच्छुक सभी देशों से कहा गया कि वे इस प्रकार के परीक्षण करने की योजनाओं पर अमल करना बंद कर दें।

सम्मेलन में कुछ समुद्र विदूषण के प्रश्न पर सामान्य सिद्धान्त भी स्वीकार किए गए। इसके समक्ष समुद्र क्षेपण पर अभिसमय का एक मसौदा था। जिसके विषय में इसमें निर्णय

†[ ] English translation.

किया गया कि उसे समुद्रतल के शांतिपूर्ण उपयोग के विषय पर संयुक्त राष्ट्र समिति के पास, अगले नवम्बर मास में लंदन में होने वाली मीटिंग में इस पर विचार-विमर्श करने से पूर्व, भेज दिया जाए।

सम्मेलन में एक जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया, वह था --मानव बस्तियों के सुधार के लिए एक फंड की स्थापना करना। यह विचार और उसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया जिसका भारतीय शिष्टमंडल ने मार्गदर्शन किया था और वह प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में देशों से कहा गया है कि वे इस प्रकार के फंड की स्थापना की दिशा में कदम उठाएं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा गया है कि वह महासभा के अगले अधिवेशन के लिए इस पर रिपोर्ट तैयार करें।

114. देशों से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने स्टाकहोम सम्मेलन में भाग लिया था।

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA LAL SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The United Nations Conference on Human Environment, which was held at Stockholm from June 5 to 16, 1972, reached a number of decisions and adopted a number of resolutions on these. The important resolutions are as follows.

The Conference adopted a Declaration on the Human Environment which lays down guide-lines for a minimum programme of agreed action for both the developed and developing countries. It recognises the important manifestations of the crisis of the environment such as inadequate water supply, ocean pollution over-urbanisation and the problem of pollution associated with poverty and under-development.

The Conference also adopted a Resolution on International Organisational Implications in which it recognised that the responsibility to protect and enhance the environment lay primarily with Govts, and could be effectively exercised at the national and regional levels. It also recognised the Sovereignty of States and the need to assist developing countries to implement environment policies compatible with their development programmes. The Resolution on organisational implications also recommended that the United Nations General Assembly establish a Governing Council for Environmenial Programmes composed of 54 members to be elected for three year terms on the basis of equitable geographical distribution. The Governing Council, which would report annually to the General Assembly through the United Nations Economic and Social Council, would have the responsibility of promoting international co-operation in the environmental field, providing general policy guide lines, keeping in view the environmental situation, promoting the contribution of the relevant international, scientific and other professional communities to the acquisition, assessment and exchange of environmental knowledge, and maintaining under continuing review the impact of national and international environmental policies and measures on developing countries, as well as the problems of additional costs that might be incurred by developing countries in the implementation of environmental programmes and projects.

The Conference also adopted a Resolution that condemned nuclear weapon tests, especially those carried out in the atmosphere. It called upon all those States intending to carry out nuclear tests to halt their plans to carry out such tests.

The Conference adopted certain general principles on the issue of pollution of the oceans. It had before it a draft

Convention on Ocean Dumping which it decided to remit to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of the Sea Bed for further consideration, prior to a discussion of it at a meeting in London next November.

An important Resolution adopted at the Conference was the one on the establishment of a fund for the betterment of human settlements. The idea as well as the resolution were put forward and piloted by the Indian Delegation and the Resolution was adopted by a big majority. It calls upon States to take steps towards the creation of such a fund, and the United Nations Secretary General has been asked to prepare a report on this for the next session of the General Assembly.

Approximately 1500 delegates from 114 countries participated in the Stockholm Conference.]

EXPLORATION OF EMERALD IN AJMER-UDAIPUR REGION BY RUSSIAN EXPERTS

372. SHRIMATI LAKSHMI :
KUMARI CHUNDAWAT :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an exploration was carried out by Russian Experts in Ajmer-Udaipur region for ascertaining the existence of Panna emerald; and

(b) if so, what are the main features of the survey report of the experts and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

BIDI AND CIGAR WORKERS ACT, 1968

373. SHRI N. H. KUMBHARE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether rhe Government have examined the working of the Bidi and Cigar Workers Act, 1968 ;

(b) whether the Government is satisfied with the working of the Act;

(c) whether the State Governments which are entrusted with the administration of Act, have taketi step to set up a machinery to secure implementation of the Act;

(d) whether the Government are aware of the short-comings in the Act which come in the way of securing implementation of the Act;

(e) if so, whether Government propose to make amendments to this Act with a view to remove the short-comings?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (e) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 is administered by the State Governments. After framing rules thereunder and setting up machinery for implementation of the Act, the State Governments concerned have brought the Act into force. However, the beedi establishment owners/associations have filed a number of petitions in various High Courts challenging the vires of the Act and stay of the operation of the Act has been granted in these cases. Appeals against the judgments of some High Courts are also pending in the Supreme Court. The State Governments have, therefore, not been able to enforce the Act fully. As such the question of amendment of the Act does not arise at this stage.

U. S. ARMS AID

374. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the U.S. Government have decided to cut off Arms Aid to India and Pakistan; and

(b) if so, the extent of the arms aid cut in the case of India as compared to Pakistan, and the reaction of Government with regard thereto?